मुख्यमंत्री ने बीसलपुर व नवनेरा बाँध भरने पर खुशी जताई

उन्होंने कहा कि मानसून में अच्छी बारिश से नियमित जलपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी

जयपुर, 24 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीसलपुर बांध का पूरा भरना अत्यंत हर्ष का विषय है। यह पहली बार है जब जुलाई माह में बीसलपुर बांध का गेट खोला गया है। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना के घटक नवनेरा बांध (इटावा, कोटा) का भरना भी जलापूर्ति के साथ ही कृषि कार्यों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहली बार लगातार दो साल बीसलपुर बाँध पूरा भरा है। इस बाँध से जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की करीब एक करोड़ की आबादी को पेयजल आपूर्ति की जाती है।**

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अंचलों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर के माध्यम से किसान सहित सभी वर्गों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानसून में अच्छी बारिश होने से निर्बाध और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि 24 जुलाई 2025 की तारीख ने प्रदेश में नया इतिहास रचा है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से पानी का स्तर बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर तक पहुंच गया। इसके बाद गेट नंबर 10 को 1 मीटर खोल दिया गया, जिससे लगभग 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई में ही बीसलपुर बांध भर गया है। साथ ही, यह पहली बार है कि लगातार दो वर्ष (2024-2025) बीसलपुर बांध भरा है। गौरतलब है कि यह बांध परियोजना जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले की लगभग एक करोड़ आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

वहीं नवनेरा बांध भी गुरुवार को पूरा भर गया। इसमें पानी का लेवल 214 आरएल मीटर पहुंच गया जिसके बाद इसके गेट नंबर 11, 12 व 13 खोल दिए गए। इससे 600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस निकासी से अपस्ट्रीम में कालीसिंध नदी के आस-पास कुंओं और भूजल के स्तर में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि बांध की कुल भराव क्षमता 226.65 मिलियन क्यूबिक मीटर है एवं बांध की वर्तमान भराव क्षमता 159.87 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

सुप्रीम कोर्ट ने मुम्बई ट्रेन धमाकों पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 24 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी सभी 12 लोगों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले पर गुरुवार को रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस याचिका

■ **लेकिन हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए सभी 12 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।**

को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले को अन्य लंबित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों में मिसाल नहीं माना जाए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस दलील पर गौर किया और स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

अनिल अंबानी की कंपनियों पर ई.डी. ने रेड की

यह कार्यवाही अनिल अंबानी की कम्पनियों द्वारा 3000 करोड़ रु. के फर्जीवाड़े को लेकर की गई है

मुंबई, 24 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी अनिल अंबानी समूह की कंपनियों एवं यस बैंक से जुड़े करीब 3000 करोड़ रुपयों के बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है।

■ **आरोप है, कि अंबानी समूह की कंपनियों ने 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से प्राप्त 3000 करोड़ रु. के ऋण में भारी हैराफेरी की थी।**

इस छापेमारी को लेकर अनिल अंबानी समूह की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है कि जिन रिपोर्टों को लेकर ईडी की कार्रवाई की जा रही है, वे रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े आठ वर्ष से ज्यादा पुराने लेन-देने से संबंधित प्रतीत होती हैं।

ईडी ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर जिन शिकायतों के आधार पर छापेमारी की है, वे अंबानी समूह की कंपनियों द्वारा लोन के दुरुपयोग, रिश्वतखोरी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी से संबंधित हैं।

सूत्रों का कहना है कि ईडी को प्राप्त हुई जानकारियां नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, बैंक आफ बड़ौदा आदि से प्राप्त हुई थीं। ईडी को पता चला है कि अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियां सार्वजनिक धन की हेराफेरी एवं वित्तीय संस्थानों को गुमराह करने की योजना में शामिल थीं।

कहा जा रहा है कि इसमें 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से करीब 3000 करोड़ रुपयों के ऋण की कथित तौर पर हेराफेरी की गई थी। इस हेराफेरी की कड़ी में, कई मामलों में औपरचारिक मंजूरी मिलने से पहले ही ऋण वितरित कर दिया गया और बैंक में आवेदन जमा होने के दिन ही राशि भी जारी कर दी गई।

इनमें ऋण पानेवाली कुछ कंपनियों की तो वित्तीय स्थिति भी कमजोर थी और उनके पास उचित दस्तावेजों की भी कमी थी। कहा जा रहा है कि रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लि. (आरएचएफएल) द्वारा दिए गए कॉर्पोरेट लोन में भारी उछाल देखने के बाद सेबी ने यह जानकारी ईडी के साथ साझा की थी।

ये कॉर्पोरेट लोन 2017-18 के 3,742.60 करोड़ रुपयों से बढ़ कर, 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए हो गए थे। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये उछाल किसी लोन डायवर्जन योजना से तो नहीं जुड़ा था।

बता दें कि ईडी की यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किए जाने के बाद शुरू हुई है।

गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी पर रिलायंस समूह द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रमोटर की कुछ निजी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए ऋण उन कंपनियों की योग्यता के आधार पर स्वीकृत किए गए थे।

फ्री ट्रेड एग्रीमैंट के मार्फत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रोवर - अब भारतीय बाजार में आसानी से आ सकेंगी, जबकि भारतीय चाय और कई कृषि उत्पाद ब्रिटिश बाजार में अब अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे क्योंकि टैरिफ में कटौती तुरंत प्रभाव से लागू होगी।

दोनों देशों के विकास की गति और बाजारों की बदलती मांग भविष्य में यह तय करेगी कि कौन कितना लाभ उठाएगा और कौन नहीं।

यह सोचना गलत नहीं होगा कि भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि और बढ़ती समृद्धि के चलते भारत में लग्ज़री कारों की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी, जबकि ब्रिटेन में भारतीय चाय और कृषि उत्पादों की मांग सीमित ही रहेगी। आखिर कोई देश कारों की तरह तेजी से चाय और सब्जियां तो नहीं खरीद सकता

यह बात स्पष्ट है कि भविष्य में ब्रिटेन को उन उत्पादों पर कम शुल्क का फायदा मिलेगा, जिनकी भारत में भारी मांग हो सकती है।

इसका यह मतलब नहीं है कि भारत नुकसान में रहेगा। भारत जैसे-जैसे आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी तेजी से विकसित होगा। उसका उद्योग और मूल्यवर्धन और अधिक उन्नत होगा। यह सब ब्रिटेन के बाज़ार में बेहतर प्रवेश पाएंगे।

साथ ही यह भी सच है कि ब्रिटेन का बाज़ार पहले से ही छोटा है और भविष्य में भारत की तुलना में और भी छोटा होता जाएगा। यही भारत का भविष्य है जो आज दुनिया के कई देशों जिनमें अमेरिका भी शामिल है, को भारत के साथ व्यापार समझौता करने को प्रेरित कर रहा है।

भारत की इसी आर्थिक संभावना को देखते हुए डॉनल्ड ट्रंप जैसे नेता भी भारत पर ज्यादा शुल्क लगाने से बचते हैं ताकि चल रही व्यापार वार्ताएं बाधित न हों। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत इसी तरह प्रगति करता रहेगा और एक बार फिर दुनिया भर के व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, जैसा कि वह ऐतिहासिक रूप से रहा है।

भागवत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

100 साल में इस तरह की बैठक कभी भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिस सद्भावनापूर्ण माहौल में हर मुद्दे पर चर्चा हुई और जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सबकी बातों को धैर्य से सुना, वह काबिले-तारीफ था।

उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान आरएसएस प्रमुख ने कई बातें कहीं। उन्होंने बताया कि सब इस बात पर सहमत हुए कि इस तरह की मुलाकातें हर राज्य में समय-समय पर होती रहनी चाहिए।

इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इंद्रेश कुमार भी शामिल हुए।

कल तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यादव, तेजस्वी यादव और अन्य नेता, इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। सभी को लग रहा है कि मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना और इस तरह चुनाव को चुराना, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद से फोकस लगातार बिहार और एस आई आर मुद्दे पर बना हुआ है।

विपक्ष रोजाना संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है और कल वे गांधी प्रतिमा से संसद के मकर द्वार तक मार्च करेंगे।

सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विपक्ष को आपत्ति है, तो वह चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जाए।

अब यह विपक्ष पर निर्भर है कि वह लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगा और उन तरीकों का विरोध कैसे करेगा, जिनके ज़रिए संविधान की अनदेखी करके, दिन-दहाड़े चुनावों में सेंध लगाई जा रही है तथा उन्हें प्रभावित किया जा रहा है।

आज निर्णय होगा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंतरिम रोक जारी रहनी चाहिए?

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति कांत ने कहा , हम कल 10-15 मिनट और लेंगे और मामले का निपटारा कर देंगे।

केन्द्र सरकार को संवैधानिक पदों, संस्थाओं व संविधान की परवाह नहीं- पायलट

सचिन पायलट ने टोंक में धन्ना तलाई के ड्रेनेज सिस्टम व सौन्दर्यीकरण का शिलान्यास किया

टोंक, 24 जुलाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकारों ने किसानों तथा गरीबों की आवाज को दबाने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, वे जनता का वोट लेकर आये हैं, परन्तु उन्हें जनता की, किसान की, खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की कोई चिन्ता नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार मनरेगा योजना लेकर आयी थी। कोरोना के समय में मनरेगा ने किसानों को, गरीबों व आमजन को सम्बल प्रदान करने का काम किया था। आज भाजपा सरकार ऐसी महत्वपूर्ण योजना को ठप्प करने का काम कर रही है। इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल बना रही हैं कि लोग इससे जुड़ ही न पायें। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान विरोधी काले कानून लाने, एम.एस.पी. लागू नहीं करने, मण्डी व्यवस्था ठप्प करने को तैयार है, परन्तु किसान यदि मुआवजा मांग ले, एम.एस.पी. लागू करने की बात कहे, फसल पर बोनस मांग ले तो सरकार देने को तैयार नहीं।

पायलट ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र सरकार को संवैधानिक पदों, संवैधानिक संस्थाओं और संविधान की कोई परवाह नहीं है। करने का काम भाजपा सरकार ने किया संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने गुरूवार को टोंक में डेढ़ करोड़ रूपये के पानी निकासी के ड्रेनेज सिस्टम एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया।

■ **कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, भाजपा सरकार मनरेगा योजना की प्रक्रिया को इतना जटिल बना रही है कि लोग इससे जुड़ ही नहीं पायें।**

पायलट ने डेढ़ करोड़ रूपये की लागत से टोंक शहर स्थित धन्ना तलाई के पानी की निकासी के ड्रेनेज सिस्टम एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास तथा विधायक मद से 10 लाख रूपये की राशि से वार्ड नं. 56 में बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि धन्ना तलाई में आज जो विकास कार्य का शिलान्यास किया है, इस कार्य के पूर्ण होने पर यहां के लोगों को गंदे पानी से निजात मिलेगी और यहां एक सुन्दर पार्क विकसित कियाा जायेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज तथा न्यू हॉस्पीटल का कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है। इससे टोंक व आसपास के लोगों को इलाज के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो विकास के कार्यो के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।

'क्या मृत मतदाताओं को भी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज़ोर देकर कहा कि हर चुनाव के लिए एक त्रुटिरहित और साफ-सुथरी मतदाता सूची तैयार चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है।

उन्होंने पूछा, "क्या पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की गई एक शुद्ध मतदाता सूची, निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं होती?" उन्होंने आगे कहा, "इन सवालों पर, कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर गंभीरता से सोचना होगा।"

मुख्य चुनाव आयुक्त की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय आई हैं जब विपक्षी दल, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) और कांग्रेस, यह आरोप लगा रहे हैं कि एस.आई.आर. प्रक्रिया के कारण 50 लाख से अधिक लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

कुमार ने उसी संविधान का हवाला दिया, विपक्ष के अनुसार, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से कुचला जा रहा है।

ज्ञानेश कुमार ने कहा, "भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र की जनती है। चुनाव आयोग को डर है कि अगर मृत लोगों के नाम पर, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम पर, डुप्लीकेट या फर्जी और विदेशी वोटरों के नाम पर वोट डाले गए, तो चुनाव प्रक्रिया भटक सकती है। इसीलिए यह समीक्षा बिहार में शुरू की गई है और इसे पूरे देश में ले जाया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा। "क्या चुनाव आयोग को ऐसे मतदाताओं को सूची से नहीं हटाना चाहिए?" चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार की मतदाता सूची से 56 लाख नाम हटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन 56 लाख नामों में शामिल हैं: 20 लाख मृतक मतदाता, 28 लाख अन्य राज्य में स्थायी रूप से चले गए लोग, 7 लाख ऐसे लोग जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं और 1 लाख ऐसे मतदाता जिनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके अलावा, लगभग 15 लाख लोगों ने सत्यापन फॉर्म वापस नहीं किया, जिससे उनकी स्थिति भी संदेह में आ गई है।

भाजपा से नाराज़ हिंदू वोटों पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के रूप में देखा जाता है। ऐसे में, अखिलेश यादव ने अपने मंदिर के वीडियो को पोस्ट करना बेहतर समझा, तथा इस बहाने सावन के पहले सोमवार को सबसे "रामा-श्यामा" भी हो गई। हालांकि यादव ने हाल ही में सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कदम बढ़ाया है, लेकिन उन्हें हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों से पहले ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

चूँकि इटावा का यह मंदिर जिसे 'केदारेश्वर धाम' नाम दिया गया है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से एक, 'केदारनाथ धाम' की तर्ज पर बन रहा है, इसलिये उत्तराखंड के संतों और साधुओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।

उनका आरोप है कि मंदिर की नकल करना केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थस्थल की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इसे "सनातन धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश" करार देते हुए कहा कि यह सदियों पुराने हिमालयी मंदिर की ऐतिहासिक धार्मिक महत्ता को कमज़ोर करने का प्रयास है।

हालांकि यादव ने इस आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन 2023 का एक पुराना वीडियो, जिसमें वे धार्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य के साथ सड़क किनारे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, हाल ही में वायरल हुआ है। इस वीडियो के जरिए उनकी हिंदू संतों के साथ कथित अभद्रता की आलोचना फिर से शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, यादव की 'सॉफ्ट हिंदुत्व' रणनीति की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही इसकी धर्मनिरपेक्ष पहचान रही है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को अक्सर मुस्लिम तुष्टिकरण के रूप में देखा गया है-खासतौर पर उत्तर प्रदेश में।

समाजवादी पार्टी के गठन से पहले, जब सपा-संस्थापक मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अखिलेश यादव की वर्तमान धार्मिक मुद्रा की विश्वसनीयता को और कमजोर करती है।

आमतौर से ऐसा माना जाता है कि जनता की स्मृति अल्पकालिक होती है और दशकों पुराने विवादों का चुनावी प्रभाव कम हो जाता है, फिर भी हाल ही में संसद मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ अखिलेश यादव की बैठक ने उनकी 'सॉफ्ट हिंदुत्व' नीति की ईमानदारी पर नये सिरे से संदेह पैदा कर दिये हैं।

यादव के 'हिंदुत्व' ब्रांड के लिये सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो पहले से ही एक शक्तिशाली हिंदुत्व प्रतीक के रूप में स्थापित हैं तथा इस प्रकार, समाजवादी पार्टी के लिए इस क्षेत्र में विस्तार की गुंजाइश सीमित दिखाई देती है।

नाबालिग का देह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईमेल कर अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी थी। इस पर वह झोटवाड़ा स्थित अपनी दुकान से घर चला गया। जहां पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त उसे डरा धमकाकर आए दिन दुष्कर्म करते थे। इसके बाद, शाम के समय पीड़िता ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय पर पता चलने पर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, पीड़िता ने अदालत को बताया कि शैतान का शराब का ठेका उसके घर के पास होने के कारण वह उसे जानती थी। शैतान ने 9 मई 2018 को उसे नींद की गोलियां देकर, परिजनों को देने को कहा। रात के समय उसने परिजनों को नींद की गोलियां दीं और शैतान से मिलने उसके यहाँ चली गई।

भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमैंट्स से 2030 तक व्यापार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गतिशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामान, सेवाओं और डिजिटल व्यापार के प्रवाह को फिर से आकार देने वाला एक रणनीतिक सहयोग है।

एफटीए का मूल उद्देश्य है शुल्कों को अभूतपूर्व स्तर पर कम करना। अब भारत से 99 प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन में बिना शुल्क के प्रवेश करेंगे, जिससे वस्त्र, रत्न और आभूषण, जूते, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पादों और मशीनरी जैसे क्षेत्रों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय निर्यातकों के लिए इसका मतलब है उच्च-मूल्य वाले ब्रिटिश बाजारों तक लगभग त्वरित पहुंच, वह भी पहले जैसी लागत बाधाओं के बिना। कपड़ा उद्योग, जो पहले से ही बड़े पैमाने पर रोजगार देता है, इस समझौते से सबसे अधिक लाभ उठाने वालों में से एक होगा, साथ ही भारत के एमएसएमई और समुद्री उत्पाद निर्यातक भी लाभान्वित होंगे।

बदले में, भारत ब्रिटेन से आने वाले 90 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्क कम करेगा, जिससे भारतीय उपभोक्ता बाजार में प्रीमियम कारों, दवाओं, स्कॉच व्हिस्की और उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट जैसे ब्रिटिश उत्पादों के लिए रास्ता खुलेगा। स्कॉच व्हिस्की और जिन जैसी ब्रिटिश वस्तुओं पर वर्तमान में 150 प्रतिशत टैक्स लगता है, जिसे तुरंत घटाकर 75 प्रतिशत और अगले दस वर्षों में 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी तरह, ब्रिटिश लग्ज़री कारों पर 100 प्रतिशत से अधिक आयात शुल्क लगता था, इसे घटाकर मात्र 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

हालांकि यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सेवाएं-जो भारत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है, भी इसका बड़ा लाभ उठाएंगी। एफटीए में आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय कंपनियों के ब्रिटेन में प्रवेश नियमों में ढील दी गई है। वहीं, ब्रिटिश सेवा प्रदाताओं को भारत के मध्यम वर्ग द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी।

एक ऐतिहासिक प्रावधान एक लंबे समय से चली आ रही भारतीय चिंता को दूर करता है, यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा भुगतान। इस समझौते के तहत, ऐसे पेशेवर अब तीन वर्षों तक इन भुगतानों से मुक्त रहेंगे, प्रत्येक कर्मचारी के लिए हजारों पाउंड की संभावित वार्षिक बचत।

यह समझौता छोटे और मध्यम उद्यमों को भी सशक्त बनाता है, जिसमें सरल कस्टम प्रक्रियाएं, 48 घंटे में क्लीयरेंस और डिजिटल व्यापार सुगमता का वादा शामिल है। सीमा-पार डिजिटल व्यापार को संरक्षित किया जाएगा, जिसमें ई-कॉमर्स ड्यूटी पर रोक, ई-कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी मान्यता और सुरक्षित डेटा प्रवाह के प्रोटोकॉल शामिल हैं।

हालांकि भारत खुलापन अपना रहा है, लेकिन डीज़ल वाहन, उच्च तकनीक इलैक्ट्रॉनिक्स और कच्चे हीरे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है, यह संकेत देता है कि भारत घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा भी कर रहा है।

एफटीए को जुलाई में भारत की कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और इसे यूके की संसद द्वारा भी जल्द ही अनुमोदित किया जाएगा। अगले 9 से 15 महीनों में इसके लागू होने की उम्मीद है।

यह समझौता केवल एक आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि यह एक साहसिक भू-राजनीतिक वक्तव्य है। जब वैश्विक व्यापार साझेदारियों का पुनर्गठन हो रहा है, भारत और ब्रिटेन एक-दूसरे के भविष्य पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र ने इस एफटीए का जोरदार स्वागत किया है और इसे भारत के उभरते व्यापार ढांचे में एक प्रमुख मील का पत्थर बताया है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है।

आरपीजी ग्रुप के वाइस चेयरमैन अनंत गोयनका ने कहा, "भारत-ब्रिटेन एफटीए दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह समझौता व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय निर्यातकों के लिए बेहतर बाजार पहुंच और अधिक निश्चितता प्रदान करेगा। हम इस व्यापक समझौते का स्वागत करते हैं, जो भारतीय व्यापारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आता है और उच्च स्तर के द्विपक्षीय व्यापार व आर्थिक सहयोग की नींव रखता है।"

महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप सीईओ और एमडी, अनीश शाह ने कहा, "भारत और ब्रिटेन के बीच यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी क्षण है। यह केवल व्यापार की जीत नहीं है, बल्कि एक आधुनिक साझेदारी का खाका है, जिसमें नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को केन्द्र में रखा गया है। जैसे-जैसे भारतीय उद्योग वैश्विक होता जा रहा है, हम इस साझेदारी के अगले अध्याय में सार्थक योगदान देने की उम्मीद करते हैं।"

फिक्की के अध्यक्ष और इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एवं एमडी, हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, "भारत-यूके एफटीए पर हस्ताक्षर भारत के व्यापार ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों का पूरक है, जिससे घरेलू उद्योग वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकें, प्रतिस्पर्धी बन सकें और मूल्य श्रृंखलाओं का अधिक प्रभावी तरीके से लाभ उठा सकें। फिक्की इस विकास का स्वागत करता है, जो एक अधिक लचीला और अवसर प्रधान व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक कदम है, जिससे दोनों देशों और उनके नागरिकों को लाभ होगा।"

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908